गुजरात में जगह जगह पर कोयले की कमी के कारण एक साथ कई गाड़ियां बन्द कर दी हैं। भाव नगर विभाग में 40 गाड़ी, महेसाना विभाग में 16 गाड़ियां बड़ौदारा विभाग में 11 गाड़ियां और अहमदाबाद विभाग में भी कई गाड़ियां बन्द कर दी गई है। एक तरफ गर्मी के दिनों की बढ़ती ट्रेन यात्रा की भीड़ को निपटाने के लिये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और दूसरी तरफ ऐसे एक ही विभाग में जिसमें कि कुल 106 गाड़ियां चलती हैं उनमें से 40 गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं। रेल मंत्रालय किस तरह से कार्य करता है, इसका यह नमूना है। अभी अभी थोड़े ही दिन पहले लोक सभा में बताया गया था कि कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कोयले के अभाव में ही इतनी गाड़ियां एक साथ एक ही विभाग की बन्द कर दी जाती है। सरकार किस ढंग से चल रही है, यह इससे प्रतीत होता है। कोयले के अभाव के कारण बिजली की भी भारी कमी देश भर में चल रही है जिससे हर क्षेत्र में उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि कोयले का उत्पादन बढ़ा करके देश का उत्पादन बढ़ाया जाय तथा देश में परिवहन भी अच्छी तरह चले यह देखा जाय। विशेषेमा रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह गर्मी के दिनों म ट्रेनें बन्द होने से यात्रियों को हो रही परेशानियों से बचाने के लिये तुरन्त ये सभी ट्रेनें चालू कर दी जायें—ऐसा प्रबंध शीघ्र ही करें।

(iv) FINANCIAL ASSISTANCE FOR POLAVARAM IN MULTIPURPOSE PROJECT IN ANDHRA PRADESH

SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI (Narasapur): The Polavaram project is a multipurpose project. It confers various benefits such as irrigation, water supply for industrial development, power generation, navigation, pisciculture and recreation etc. This is a modification of Ramapadasagar project. It is based on the developed technique. It is 1½ Km. upstream of R. P. S. alignment. The releases from Inchampalli and Lower Sileru uptream hydroelectric schemes have been found sufficient to cater to the needs of this project. A project report was sent to the Government of India for Stage I, Phase I of Polavaram project. In the light of the Godavari water disputs tribunal award, an analysis has been made in regard to the quantum of water available for the project and the existing delta requirements.

The Central Water Commission examined the scheme report of 1978. The team visited the dam site on June 3, 1980 and offered suggestions. It will also revive and give fillip to river Godavari which has a glorious tradition of navigation. It will also increase inland canal transport and commercial activities. It will create tremendous capacity for power generation. The estimated cost of the project under various components is Rs. 550 crores.

The irrigation facilities arising from the project will produce additional foodstuffs valuinges. Rs. 175 crores per year, 86 MW and 430 MW Power, inland water transport. There is nothing practically in the way of sanctioning of the project and the work is to be taken up earnestly to usher in a new era of prosperity for the State. The investigation of the dam has been completed. Some reinvestigation and hydrology of Godavari river basin are being worked out, the designs are under scrutiny and replies to the Central Water Commission are being prepared and estimates recast. All these will be completed by the end of June, 1981.

During the sixth Plan period, it is proposed to complete infra-structure works. It includes spill way work, rock clearance, excavation of huge spill channel and the setting up of heavy machinery workshop.

This stupendous work can be achieved only with the help and assistance of the Union Government. I urge upon the Government to come in a big and earnest way to help the State achieve this mammoth project to usher in an era of economic upsurge and welfare and happiness of the people of Andhra Pradesh.

(v) EXPLOITATION OF WORKERS ENGAGED IN NITRE (SHORA) INDUSTRY

श्री बी० डी० सिंह : (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान प्रदेशों में लाखों की संख्या में लोग शोरा निकालने का काम करते हैं । ये लोग निपट, निर्धन एवं असंगठित श्रमिक हैं । हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, करनाल, हिसार, सिरसा तथा अम्बाला आदि जिलों में यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है । इस कार्य में लगे लोगों का पूंजीपतियों द्वारा अनेक प्रकार से शोषण होता है । शोरा निकालने की भूमि का ठेका प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में सरकार द्वारा सीधे उन पूंजीपतियों को दे दिया जाता है जो शोरा के शोधन का कार्य करते हैं । शोरगर श्रमिक को इन उद्योगपतियों द्वारा शोरा निकालने का ठेका दिया जाता है । शोरगर श्रमिक ग्रीष्म ऋतु की भयंकर लू और शीत ऋतु की कड़कती ठन्ड में अपने परिवार सहित कठिन परिश्रम करके शोरा तैयार करते हैं परन्तु उसका लाभ उद्योगपति उठाता है। श्रमिकों को अपने परिश्रम का मात्र एक चौथाई अंश प्राप्त होता है, जबकि पूंजीपति तीन-चौथाई अंश हड़प कर जाता है । शोरगर श्रमिकों का यह शोषण सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है ।

मैं सरकार से सविनय आग्रह करूंगा कि इन गरीब परिवारों की राहत के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जायें । भूमि का ठेका पूंजिपतियों को न देकर सीधे श्रमिकों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से दिया जाय । इन श्रमिकों के पास जीविकोपार्जन के लिये कोई अन्य साधन नहीं है । इन श्रमिकों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाय और उन्हें लघु-उद्योग की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, बैंकों से आवश्यक आर्थिक सहायता समुचित ब्याज पर दी जानी चाहिये । श्रमिक समितियों को भूमि का ठेका पांच वर्ष अथवा अधिक लम्बी अवधि के लिए स्थायी तौर पर दिया जाय जिससे श्रमिक एक स्थान पर स्थायी तौर से रहकर अपने बच्चों की शिक्षा आदि की भी कुछ व्यवस्था कर सकें । शोरे की तोल का भी कुछ गलत तरीका इस्तेमाल होता है । पूंजीपति 110 किलोग्राम को 1 क्विंटल मानकर क्रय करता है । अनुबन्ध के नाम पर सादे कागज पर अशिक्षित तथा अनभिज्ञ श्रमिकों का हस्ताक्षर कराकर उनको बधुआ मजदूर बना लिया जाता है और भविष्य में दसियों वर्ष तक उसी पूंजीपति के साथ काम करने को वे बाध्य हो जाते हैं ।

अतएव एक जांच समिति के द्वारा शोरे उद्योग की कार्यप्रणाली का विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिये तथा इसमें आवश्यक सुधार करके शोरगर श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये

(vi) STEPS FOR A BREAKTHROUGH IN FISH CULTURE ENTERPRISES, PARTICULARLY IN TAMIL NADU.

SHRI CUMBUM N. NATARAJAN (Periyakulam) : India with a population of 68.5 crores is in a steadily worsening state of